उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को दी गई राशि

1361. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार राज्य में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृतिक विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधान मण्डल के अधिनियमों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं और इसलिए यह संबंधित राज्य सरकारों की प्रारम्भिक जिम्मेवारी होती है कि वे उन्हें उपयुक्त योजनागत और योजनेत्तर अनुदान प्रदान करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को केवल विकास के लिए अनुदान देता है और वह भी केवल उनकी आवश्यकताओं के एक भाग के लिए होता है। आयोग ने 8वीं योजना में राज्य विश्वविद्यालयों के लिये योजनागत सहायता के स्तर में छूट दी है।

दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, को उत्तर प्रदेश राज्य में संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबन्ध संस्थान भी इस राज्य में स्थापित किए गए हैं।

(ख) लखनऊ में बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए संसद द्वारा पहले से ही कानून बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के प्रश्न पर जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Annual expenditure of Maulana Azad Education Foundation

1362. **SHRI SANATAN BISI:** Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what is the quantum of Annual Expenditure of the Maulana Azad Education Foundation during the years 1993-94 and 1994-95 incurred for coaching students;

(b) what is the number of student beneficiaries belonging to communities of Educationally Backward Section; and

(c) what are the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) The Foundation has not taken up any schemes for coaching students. Therefore, the question of incurring any expenditure does not arise.

(b) and (c) Does not arise.

**Written Answers to Starred and Unstarred Questions set for the 14th August, 1995*

उत्तर प्रदेश स्थित मुक्त व्यापार क्षेत्र

181. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश स्थित मुक्त व्यापार क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उत्तर प्रदेश से बढ़ते हुए निर्यात को देखते हुए नये मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये क्षेत्र कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्): (क) से (घ) नोएडा, उत्तर प्रदेश में एक निर्यात प्रोसेसिंग जोन कार्यरत है। निधियों की उपलब्धता और मौजूदा निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में बुनियादी सुविधाओं को अनुकूल बनाने की आवश्यकता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का देश में नए जोन स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा और संयुक्त क्षेत्र/गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्यात प्रोसेसिंग जोनों की स्थापना हेतु हाल ही में अनुमति दी है।

---

*The sitting of the Rajya Sabha on Monday the 14th August, 95 was cancelled. Answers to Questions put down in the lists for that day were laid on the Table of the House on Wednesday, the 16th August, 1995.